

(13) अ०  
३१०५।०१।०१।०१  
प्रेषक,

डॉ जे०बी० सिन्हा,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,  
गोमती नगर लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 06 अप्रैल, 2011

विषयः- प्रदेश में उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चयनित राज्य राजमार्गों का सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्रावि-18(182)/2009-10/उपशा/511/लखनऊ दिनांक 11-01-2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के शासी परिषद द्वारा समय-समय पर चयनित राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन, इन मार्गों को लोक निर्माण विभाग से उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

I- शासी परिषद द्वारा चयनित निम्न लिखित राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से कराये जाने हेतु निजी विकासकर्ता के चयन के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है :-

मार्ग का नाम :-	राज्य राजमार्ग संख्या	लम्बाई किमी० में
इटा-दुण्ड-फैसलदीकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण लखनऊ।	इटावा-मैनपुरी मार्ग	83
2.	अलीगढ़-मथुरा मार्ग	80
3.	एटा-दुण्डला मार्ग	31
4.	एटा-शिकोहाबाद मार्ग	85
5.	वाराणसी-भदोही-गोपीगंज मार्ग	87
6.	ताड़ीघाट-बारा मार्ग	99
7.	एन०एच०-२८ के किमी० १६० से प्रारम्भ होकर कलवारी-बड़हलगंज-लार-गुठनी मार्ग	72
8.	मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग	59

II- उपर्युक्त 08 राज्य राजमार्गों को लोक निर्माण विभाग से उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को इस शर्त के साथ निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा कि मार्गों को निजी विकासकर्ता को हस्तान्तरित किये जाने तक उनका अनुरक्षण पूर्ववत् लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जाता रहेगा।

परियोजना महाप्रबन्धक III- सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण कराये उ०प्र० राज्य राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित मर्दों पर होने वाले व्यय का वहन निजी क्षेत्रीय ग्राम्यालय, मुजफ्फरनगर विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित मर्दों पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा:-

(क) मार्ग पर यूटीलिटी शिपिटंग, टोल प्लाजा, जन सुविधाओं जैसे आबादी भृष्ट में अतिरिक्त रार्टिस लेन, नाली, बस सेक्टर, शौचालय इत्यादि के निर्माण एवं बायोसेल्स जैसे

निर्माण तथा सड़क को ढौड़ा करने हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण तथा मार्ग के उच्चीकरण में आने वाले वृक्षों के कटान एवं पुनर्वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय।

(ख) वायविलिटी गैप फन्डिंग नियमानुसार अनुमत्य की जायेगी।

IV- परियोजना क्षेत्र में आने वाले वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु सक्षम प्राधिकारी/भारत सरकार से वन्य (संरक्षण) अधिनियम-1980, भारतीय वन अधिनियम एवं प्रदेश के प्रचलित अन्य प्राविधान यथा-वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम-1976 एवं समय-समय पर प्रचलित अन्य संवैधानिक अधिनियम के अन्तर्गत पुरानुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे क्षेत्र जो सेंकचुरी/नेशनल पार्क के अन्दर अवस्थित होंगे, उन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य के लिये राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड/मा० उच्चतम् न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इन प्राविधानों की जानकारी निजी विकासकर्ता को भी उपलब्ध करादी जाय।

V- परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित किसी बिन्दु पर उच्चानुमोदन वांछित हो तो नोडल अधिकारी द्वारा अवस्थापना विकास विभाग के माध्यम से अवस्थापना विकास विभाग के विभागीय मंत्री के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

3- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-425ई/23-11-2010-1/4(उपशा-3)/2008, दि० 14-05-2010 में उल्लिखित 15 राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पर कराये जाने हेतु सेद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था चूंकि इनमें से निम्नलिखित 02 राज्य राजमार्ग सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पद्धति पर फाइनेंशियली वायविल नहीं पाये गये हैं, अतः इन मार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण सार्वजनिक-निजी-सहभागिता से न कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र० सं०	मार्ग का नाम	राज्य राजमार्ग संख्या	लम्बाई किमी० में
1	सुल्तानपुर-आजमगढ़-बलिया मार्ग	34	227.45
2	बदायूं-विल्सी-इरलामनगर-बहजोई-सम्मल-हसनपुर-गजरौला मार्ग	51	209.130

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० जे०बी० सिन्हा)

सचिव।

संख्या-91ई/23-11-2011-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, अवस्थापना विकास विभाग/नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- सदस्य, प्रशासन/वित्त, उ०प्र० राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, गोमतीनगर लखनऊ।
- वित्त व्यय (नियन्त्रण), अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
- न्याय (रिट) अनुभाग-6/वन अनुभाग-2/लोक निर्माण अनुभाग-1/2/10/12
- देव मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- देव अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच०एन०पी० कुशलाहा)

अनु सचिव।